रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या 2079/2009

लियाकत और अन्य .... अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य .... प्रत्यर्थी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313 - अभियुक्त से परीक्षण करने की शक्ति - दंड संहिता के उपबंधों के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा का आदेश -है - उच्च न्यायालय ने मामले को आगे विचारण हेतु विचारण न्यायालय को यह कहते हुए प्रतिप्रेषित किया कि अभिलेख पर सामग्री से अभियुक्त के खिलाफ पेश होने वाली विभिन्न तात्विक परिस्थितियों को धारा 313 के तहत अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया था। अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः धारा 313 के तहत अभियुक्तों की दोषपूर्ण परीक्षण अपने आप में विचारण को दूषित नहीं करती है- यह स्थापित करने का बोझ अभियुक्त पर है कि उनके खिलाफ

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाले सभी प्रेरक साक्ष्यों और दोषारोपण सामग्री से अवगत नहीं होने से पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है - तथ्यों पर, न्यायालय ने अभियुक्तों को हुई घटना, घटनाओं के क्रम और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के बारे में विस्तार से अवगत कराया था- अभियुक्तों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया था और न ही उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सवाल उठाया था - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है- गुणागुण के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय

एम. याई. इकबाल, न्यायाधीश

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 304/2003 में पारित 4 फरवरी, 2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्रतिप्रेषित है जिससे उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.07.1999 को दोपहर 2.00 बजे, राजपुरा निवासी मुस्ताक खान ने पुलिस स्टेशन दुधवाखारा में एक लिखित टाइप की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया कि उसकी दो बेटियों, जुमिला और बुल्केश की शादी 11/6/1993 को ग्राम झरिया के दो भाईयों लियाकत और जाकिर से हुई थी। शादी के बाद, उनकी बेटियों ने बताया कि उनके ससुर अजीम खान और सास जन्नत उन्हें दहेज के लिए परेशान करते थे, और इसलिए, जब भी वे आते थे, सूचनाकर्ता दहेज की आवश्यक वस्तुएं दे रहा था। यह आगे आरोप लगाया गया कि लगभग तीन साल पहले, जब लियाकत विदेश गया था, तो 40, 000/- रूपये की मांग की गई थी और सूचनकर्ता ने अपने घरेलू सामान को गिरवी रखने के बाद पैसे देने की व्यवस्था की थी। फिर भी बेटियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, यहां तक कि उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता था।उसकी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि लगभग दो महीने पहले लियाकत (मृत बेटी जुमिला का पति) विदेश (दुबई) से लौटा था और उसने भैंस की मांग की थी, जिससे जुमिला ने इस आशय से अवगत कराया था कि अगर उसे भैंस नहीं दी गई तो उसे मार दिया जाएगा। हालाँकि, सूचनाकर्ता एक गाय का प्रबंधन कर सका और उसने अपनी बेटी को एक गाय के साथ उसके ससुराल भेज दिया। श्री खान ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 23.7.1999 पर उन्हें जानकारी मिली कि

जुमिला की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वह अपने भाई सत्तार खान के साथ झरिया गए, तब तक रात हो चुकी थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। जुमिला का शव पहले ही दफनाया जा चुका था और उसे शव नहीं दिखाया गया था। आरोप है कि उस वक्त उनकी दूसरी बेटी बुलकेश बेहोश थी, इसलिए वे उसे अपने साथ ले आए।

3. 24.7.1999 को, होश में आने के बाद, बुलकेश ने खुलासा किया कि तीनों अभियुक्तों ने जुमिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसे उसने देख लिया था और परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गई। उसने यह भी खुलासा किया कि अभियुक्तों ने उसे भी मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं जानती कि उसकी हत्या कैसे नहीं हुई और तीन लोगों ने भैंस की जगह गाय ले जाने के कारण जुमिला को पीट-पीटकर मार डाला। यह जानने पर सूचनाकर्ता मुस्ताक खान अपने भाई सत्तार, इनायत खान, नवाब खान, याकूब खान, वाहिद अली, भंवरू खान और कासम खान के साथ झरिया गए और बुलकेश द्वारा बताई गई बातें बताईं। इसके बाद, तीनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उन्होंने सामूहिक रूप से जुमिला की हत्या कर दी थी, जो उनकी गलती थी और उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए।

4. उसकी रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आई.पी.सी.') की धारा 498-ए, 304 बी और 201 के तहत अपराध के

लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, घटनास्थल का नक्शा और हालात मौका तैयार किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, दस्तावेज जब्त किए गए, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के उपरान्त, अभियुक्तों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

5. विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 या वैकल्पिक धारा 302/34 सपठित धारा 201 और 498ए के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए और मुकदमा शुरू किया गया। विचारण के दौरान, 9.5.2000 तक कुछ पांच गवाहों के बयान दर्ज किये गये। इसके बाद, आरोपी लियाकत को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा सका और उन गवाहों से दोबारा पूछताछ कर नए सिरे से सुनवाई की गई, जिनके बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। यह ताज़ा परीक्षण 9.10.2000 को शुरू हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 13 गवाहों से परीक्षण किया और साक्ष्य के रूप में लिखित रिपोर्ट, साइट मैप, शव का मेमो, पंचायतनामा, इनायत खान का बयान, जब्ती मेमो, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि सहित कई दस्तावेज प्रदर्श किए गए।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में, 'सी.आर.पी.सी. ') के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किये गये, जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का खंडन किया है। अभियुक्त अजीम खान (मृतक जुमिला

के ससुर) ने बताया कि उसका बेटा लियाकत दुबई में रहता था। लियाकत की पत्नी उसे दुबई ले जाने के लिए कहती थी, लेकिन वहाँ आवास की अनुपलब्धता के कारण, उसने उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थता दिखाई। इसलिए उसने अपनी चुन्नी की मदद से पंखे के हुक से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने उसके पैतृक घर पर जानकारी भेजी और उसके पिता और पिता के बड़े भाई मृतक की माँ और भाभी के साथ गाँव झरिया आए, और जुमिला को उनकी उपस्थिति में दफनाया गया। कुछ लोगों के इशारे पर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कभी भी जुमिला और उसके पिता से दहेज की मांग नहीं की। अन्य अभियुक्तों ने भी यही बात कही।

7. विचारण न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अभियुक्त लियाकत को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के लिए, उसे एक साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। और आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास और 500 रूपये की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य अभियुक्त अजीम खान और जन्नत को आईपीसी की धारा 302/34 के

तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास से गुजरना होगा। अभियुक्त अजीम खान और जन्नत को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत एक साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने की चूक में प्रत्येक को तीन महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। और उन्हे आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 500 रूपये की सजा सुनाई गई थी। सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

8. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), चुरू द्वारा पारित फैसले से असंतुष्ट होकर, अभियुक्तों ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष उपरोक्त फैसले को चुनौती दी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, अभियुक्त अजीम खान की मृत्यु हो गई और उनकी अपील को समाप्त करने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और मामले को आगे की सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय में भेजते हुए कहा कि वर्तमान मामले में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से अभियुक्त के खिलाफ दिखाई देने वाली विभिन्न तात्विक परिस्थितियों को

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त के सामने नही रखा गया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि :-

> "... तब सवाल यह है कि परिणाम क्या होता है, यानी अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री मौजूद होने के बावजूद, जो अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान में, विद्वान निचली अदालत ने कुछ निश्चित या कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ, रखने में चूक कर दी है। केवल इसी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या क्या हर मामले में, जहां इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभिलेख पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, फिर भी उसे कुछ ऐसी परिस्थितियों पर भरोसा करके दोषी ठहराया गया है जो नियम के रूप में हर मामले में धारा 313 के तहत अभियुक्त को नहीं दी जाती हैं, विचारण को ख़राब माना जाना चाहिए और मामले को विद्वान विचरण न्यायालय को वापस भेज दिया जाना चाहिए या क्या अभियुक्त के लिए छोड़ी गई परिस्थितियों की आवश्यकता और महत्त्व पर इस अर्थ में विचार करना

आवश्यक है कि दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाना चाहिए यदि उन परिस्थितियों को छोड़कर भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। हमें इस बात पर विचार करना है कि इन विभिन्न विकल्पों में से किसे उन परिस्थितियों में चुना जाए, जहां धारा 313 के तहत आरोपी के बयान में कुछ परिस्थितियां को नहीं रखा गया है। किसी भी अन्य सीधे-सीधे फार्मूले को निर्धारित करने से कभी अभियोजन पक्ष पर और कभी-कभी अभियुक्त पर बहुत कठिनाई होगी। केवल इस तथ्य के आधार पर अभियुक्त को छूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि धारा 313 के तहत उस पर सभी सबूत नहीं रखे गए हैं, भले ही अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, क्योंकि उस स्थिति में बेईमान अभियुक्त द्वारा धारा 313 के तहत बयान में चूक करने और जघन्य अपराधों में भी उन्मुक्ति का दावा करने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जाता है। इसी तरह, जहां अभियुक्त के खिलाफ अभिलेख में कोई सामग्री नहीं है, तो भी अभियुक्त से उचित सवाल नहीं पूछने में अधिकारी की चूक के लिए मुकदमे को लंबा नहीं किया जा सकता है।"

9. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि :-

> "मामले से अलग होने से पहले, यह देखा जा सकता है कि धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लापरवाह तरीके के कारण मामले को आगे के परिणाम के साथ प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्तों मे से एक, जो जेल में है और बिना किसी गलती के निरंतर लंबे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम आरएचजेएस कैडर के अधिकारियों को धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयानों की उचित रिकॉर्डिंग के महत्व को जानना चाहिए, जैसा कि निर्णयों की श्रृंखला में उजागर किया गया है, जिनमें से कुछ को इस निर्णय में देखा गया है। टिप्पणियों को संबंधित अधिकारी को भेजा जा सकता है और यदि माननीय मुख्य न्यायाधीश कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उचित समझते हैं तो उन्हें माननीय के संज्ञान में भी लाया जा सकता है।"

10. इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा दो अभियुक्तों द्वारा वर्तमान अपील। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियुक्त अजीम खान की उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो गई।

11. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री पल्लव शीशोदिया और राजस्थान राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत भट्ट को सुना है और विचारण न्यायालयों से प्राप्त मूल अभिलेख सहित हमारे सामने रखे गए कागजातों का अध्ययन किया है।

12. श्री सिसोदिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया कि धारा 313, सीआरपीसी, 1973 के तहत एक अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य अभियुक्त को लाभ पहुंचाना है और उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत डी अल्टरम पार्टेम (दूसरे पक्ष को सुनना) के अनुपालन में किसी भी स्थिति मे डालना नहीं। उन्होंने **बसवराज आर. पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य**, (2000) 8 एससीसी 740 और **अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2007) 12 एससीसी 341 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

13. यह तर्क देते हुए कि अपीलीय न्यायालय की आपराधिक अपील पर सुनवाई के लिए दोबारा परीक्षण का आदेश देने की शक्ति के परिणामस्वरूप पूरे मामले का नए सिरे से परीक्षण होगा, जिसका आदेश केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में दिया जाना चाहिए, जब न्याय की विफलता को रोकने के लिए नए सिरे से परीक्षण का ऐसा क्रम

अपरिहार्य हो जाता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शीशोदिया ने इस न्यायालय के उक्त फैसलो पर भरोसा किया- **मोहम्मद हुसैन @जुल्फिकार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)**, (2012) 9 एससीसी 408, **एम.पी. राज्य बनाम भुराजी और अन्य**, (2001) 7 एससीसी 679 और **गणेश बनाम शरणप्पा और अंन्य** (2014) 1 एससीसी 87।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त अपीलार्थियों के स्पष्टीकरण के लिए अपने मामले और/या तात्विक साक्ष्य या परिस्थितियों को रखने में कोई बड़ी चूक नहीं दिखाई देती है। उन्होंने अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया कि अभियुक्त अपीलार्थियों ने इसे समझाया है और/या सभी तात्विक पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह की है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई आंशिक प्रतिप्रेषण की प्रक्रिया तथ्यों पर भी उचित नहीं है, कानून में बहुत कम, विशेष रूप से जब अभियुक्त अपीलार्थियों ने यह शिकायत नहीं उठाई है कि कथित रूप से अभियुक्त के विरुद्ध तात्विक साक्ष्यों और/या परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर न दिए जाने से मुकदमा ख़राब हो गया है। श्री शीशोदिया ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में यह विफलता, यदि कोई हो, का समाधान अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलार्थियों के वकील से स्पष्टीकरण मांगकर किया जा सकता है।

15. अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **फहीम खान और एक अन्य बनाम बिहार राज्य**, (2011) 13 एससीसी 147 के मामले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया था।

16. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे कार्यवाही की कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की निष्पक्ष जाँच की जाती है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे कार्यवाही की कि विचारण न्यायालय ने इसका इस्तेमाल अभियुक्त के खिलाफ किया है और उन परिस्थितियों पर विचार किया है, अर्थात कि कथित आत्महत्या के तुरंत बाद, अभियुक्तों ने उसकी अप्राकृतिक मौत के बाद पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि धारा 174 के तहत जांच नहीं हो सकी। उच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया हैः-

> "यदि वर्तमान मामले पर उपरोक्त दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, जैसा कि हमने पाया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ इस्तेमाल किया है और परिस्थितियों पर विचार किया है, अर्थात कि

कथित आत्महत्या के तुरंत बाद अभियुक्तो ने पुलिस को उसकी अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप धारा 174 के तहत जांच नहीं की जा सकी और अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।इसी तरह, विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी/4 ए और पीडब्ल्यू 10 के बयान पर भरोसा किया है कि हालात मौका में, दरवाजा अंदर से बंद किया गया था और बाहर से धक्का दिए जाने पर खोला गया था।इसी तरह, विद्वान 40 विचारण न्यायालय ने यह भी माना है कि घटनास्थल के नक्शा प्रदर्श पी/4 पर पाइंट ई 9 इंच मोटी दीवार में 15 इंच x 15 इंच का एक छेद नए सिरे से बनाया गया है, यह दिखाने के प्रयास में कि यह आत्महत्या का मामला है और अभियुक्त की ओर से मृतक को बचाने का प्रयास दिखाने के लिए छेद किया गया है, जबकि इसे खोलने का कोई औचित्य नहीं था और इस तरह आत्महत्या की झूठी कहानी पेश की गई है।इसी तरह विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी माना है कि मृतक का पति होने के बावजूद अभियुक्त लियाकत को घटना के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उसे केवल 15.5.2000 पर

गिरफ्तार किया जा सका है और अभियुक्त का फरार होना भी उसके दोषी होने की पुष्टि करता है। हमारे विचार में, इस संबंध में अभिलेख पर सामग्री प्रदर्श पी/21 है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए वारंट प्राप्त किया गया है, तथ्य यह है कि अभियुक्त के खिलाफ धारा 299 के तहत चालान दायर किया गया था और उस मुकदमे में 5 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और फिर अभियुक्त लियाकत की गिरफ्तारी के बाद, मामले का पुनः विचारण किया गया। फिर हम यह भी पाते हैं कि विद्वान लोक अभियोजक ने इस परिस्थिति पर जोर दिया है कि जैसा कि मुस्ताक पीडब्ल्यू 1 ने बयान दिया है कि जुमिला की मृत्यु के बारे में जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी और उसे अभियुक्त के खिलाफ दोषी ठहराने वाली परिस्थिति के रूप में दफनाया गया था। हमने पाया है कि धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान में इन सभी परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है और वे परिस्थितियाँ अपने आप में और साथ ही अभिलेख पर मौजूदा सामग्री के संयोजन में भी हैं, जिसके संबंध में हम किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, ऐसा न हो कि यह किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले, इस पहलू पर तात्विक प्रभाव डालता है कि क्या अभियुक्त/अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है या वे बरी होने के हकदार हैं।

17. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी, विचारण न्यायलय के फैसले को रद्द कर दिया और अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के चरण में मामले के पुन विचारण करने और उनके खिलाफ दिखाई देने वाली सभी परिस्थितियों के संबंध में अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

18. प्रथमदृष्टया, हम उच्च न्यायालय द्वारा मामले को पुनः विचारण के लिए विचारण न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। संहिता की धारा 313 निम्नानुसार हैः-

"313. अभियुक्त का परीक्षण करने की शक्ति:

(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय - (क) किसी भी स्तर पर, अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना, उसके सामने ऐसे प्रश्न रख सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझता है;

(ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों से परीक्षण किए जाने के बाद और अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, मामले पर आम तौर पर उससे पूछताछ करेगाः बशर्ते कि समन-मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया है, वह खंड (बी)के तहत उसके परीक्षण को भी समाप्त कर सकता है।

(2) जब अभियुक्त से उप-खंड (1) के तहत पूछताछ की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके, या उनके गलत उत्तर देकर स्वयं को दंड का भागी नहीं बनाएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या विचारण में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध, जो ऐसे उत्तरों से पता चले कि उसने किया है, की जांच या विचारण में उसके पक्ष या उसके खिलाफ साक्ष्य दिया जा सकता है।

(5) न्यायालय प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की मदद ले सकता है जिन्हें अभियुक्त के समक्ष रखा जाना है और न्यायालय इस धारा

के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

19. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि धारा का उद्देश्य किसी अपराध के अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाने का अवसर देना था। धारा 313 की उप-धारा (1) न्यायालय को अभियुक्त से ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार देती है जो विचारण के लिए जाँच के चरण में आवश्यक समझा जाता है। साथ ही यह एक कर्तव्य अधिरोपित करता है और न्यायालय के लिए उससे पूछताछ करना अनिवार्य बनाता है पर आम तौर पर जब अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों की परीक्षा पूरी कर लेने पर और अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए बुलाये जाने से पहले। निर्विवाद रूप से, अभियुक्त का ध्यान अभिलेख पर मौजूद प्रेरक साक्ष्य या परिस्थितियों की ओर आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए, यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो। संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य अभियुक्त को अभिलेख पर आई अपराध संलिप्तता की सामग्री को समझाने का अवसर देना है। संहिता की धारा 313 का दायरा और उद्देश्य इस न्यायालय के समक्ष कई निर्णयों में विचार के लिए आया, जिनमें से कुछ पर वर्तमान मामले के लिए चर्चा की गई है।

20. **शरद बर्धी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**, एआईआर 1984 एससी 1622 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जब अपीलार्थी को धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलार्थी या उसके माता-पिता द्वारा मृतक के साथ किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में उसके परीक्षण के दौरान कोई सवाल नहीं पूछा गया है और यदि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त के विचारण में परिस्थितियों को रखकर स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है, तो इसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

21. **शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य** (1973) 2 एससीसी 793 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संहिता की धारा 313 के प्रावधान पर विचार किया। फैसला लिखते हुए, न्यायाधीश कृष्ण अय्यर, न्यायाधीश ने कहाः-

> "16. हालाँकि, यह मौलिक कानून है कि कैदी का ध्यान प्रत्येक प्रेरक सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझाने में सक्षम हो सके। यह आपराधिक विचारण की बुनियादी निष्पक्षता है और इस क्षेत्र में विफलताएं विचारण की वैधता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती हैं, अगर परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता हुई है।हालाँकि, जहाँ ऐसी चूक हुई है, वह

वास्तव में कार्यवाही को दूषित नहीं करती है और इस तरह के दोष के कारण होने वाले पूर्वाग्रह को अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। अभियुक्त के सामने साक्ष्य सामग्री नहीं रखे जाने की स्थिति में, न्यायालय को आम तौर पर ऐसी सामग्री पर विचार करने से बचना चाहिए। अपीलीय न्यायालय के लिए यह भी खुला है कि वह अभियुक्त के अधिवक्ता से यह दिखाने के लिए कहे कि अभियुक्त के पास उसके खिलाफ स्थापित परिस्थितियों के संबंध में क्या स्पष्टीकरण है, लेकिन उसके समक्ष नहीं रखा और यदि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों का कोई प्रशंसनीय या उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि कोई स्वीकार्य उत्तर मौजूद नहीं है और भले ही अभियुक्त से विचारण न्यायालय में उचित समय पर पूछताछ की गई हो, वह उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोई अच्छा आधार प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होता, जिन पर विचारण न्यायालय ने इसकी दोषसिद्धि के लिए भरोसा किया था। ऐसे मामले में, न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि हालांकि धारा 342, सीआरपीसी के अनुपालन के संबंध में एक गंभीर अनियमितता हुई है, लेकिन यह

नहीं दिखाया गया है कि चूक ने अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है।"

22. **एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)** (1976) 2 एससीसी 819 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

"22.दं.प्र.सं. 1898 की धारा 342 अदालत को यह कर्तव्य देती है कि वह किसी भी जांच या मुकदमे में अभियुक्त से सवाल पूछे ताकि वह अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या कर सके। इससे यह आवश्यक परिणाम निकलता है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक तात्विक परिस्थिति को उसके सामने विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से रखा जाना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है जो मुकदमे को दूषित करती है यदि यह दिखाया जाता है कि इसने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है। यदि अनियमितता, वास्तव में, न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती है, तो इसे संहिता की धारा 537 के तहत ठीक किया जा सकता है।

23. मौजूदा मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मिल्स से माल के वास्तविक निकास का समय अभियोजन साक्ष्य में दिखाई देने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। दरअसल, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए अपनी दलीलें पेश कीं कि सामान 11 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले गुड्स शेड तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए, धारा 342 को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अभियुक्त के परीक्षण के दौरान इस परिस्थिति को साफ और स्पष्ट रूप से रखे। ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। अभियोजन पक्ष की ओर से एक और चूक से इस अनियमितता की गंभीरता और बढ़ गई। वह चूक तीन महत्वपूर्ण गवाहों को पेश करने में विफलता थी, अर्थात्, ट्रक चालक चिरंजीलाल, मार्कर मुकुंद लाल और रेलवे गेट क्लर्क ओम प्रकाश, अपने रिकॉर्ड के साथ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के कैलेंडर में उद्धृत किया गया था और उनके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के साथ पेश होने की आवश्यकता थी। लेकिन बाद में, बिना किसी कारण के, उन्हें छोड़ दिया गया। ये वे व्यक्ति थे जो गुड्स

शेड में इन वस्तुओं की प्राप्ति के संबंध में सबसे अच्छा और प्रत्यक्ष साक्ष्य दे सकते थे। इस साक्ष्य को प्रस्तुत न करने से निश्चित रूप से अपीलार्थी के निष्पक्ष विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

24. श्री एच.आर. खन्ना इंगित करते हैं कि धारा 342 के तहत इस परिस्थिति को परीक्षण में रखने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण अपीलार्थी के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का सवाल नीचे के न्यायालयों में नहीं उठाया गया था, और परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को अब इसे उठाने से रोक दिया गया है।"

23. **असरफ अली बनाम असम राज्य**, (2008) 16 एससीसी 328 के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"21. संहिता की धारा 313 न्यायालय को यह कर्तव्य देती है कि वह अभियुक्त सेउसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जांच या परीक्षण प्रश्न करे। यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक तात्विक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से

उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो परीक्षण को दूषित करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह था।

22. संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।यदि साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ एक बिंदु महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी पर आधारित होनी है, तो यह सही और उचित है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी प्रेरक सामग्री पर कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है, वह विचारण को दूषित कर देगा। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर हैं कि क्या वे न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बने हैं।इस न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) को देखते हुए एस. हरनाम सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1976) 2 एससीसी 819 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया

था। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपने प्रासंगिक तथ्यों में प्रेरक सामग्री का संकेत न देना अभियोजन मामले की भेद्यता को बढ़ाता है।धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना एक उद्देश्यहीन अभ्यास नहीं है।

24. **परमजीत सिंह @पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य**, (2010) 10 एससीसी 439 के मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के विचारों पर विचार करने के बाद पैरा 13 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"13. हालाँकि दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो सकती है, लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें वीभत्स तरीके से गंभीर अपराध किया गया हो का फैसला करते समय न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अभियोजन पक्ष का मामला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और इसे अभियुक्त द्वारा पेश किए गए बचाव मे कमजोरी से कोई ताकत नहीं मिल सकती है। हालांकि, एक झूठे

बचाव को केवल न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ अपने आप में पूर्ण हैं। इस न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक साक्ष्य पर भी चर्चा की जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः (एससीसी पृष्ठ 185, पैरा 153)

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

* * *

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की अनुमति वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखना चाहिए पूरी मानवीय संभावना है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।(उद्धरण पर जोर दिया गया)

25. **एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2012) 2 एससीसी 648 के मामले में, उपबंध फिर से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"61. उपरोक्त से, कानूनी स्थिति इस प्रकार प्रतीत होती हैःअभियुक्त को उसके विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए दोष सिद्ध करने वाले साक्ष्य और सामग्रियों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वह ऐसे साक्ष्य और सामग्री को समझाने और उसका जवाब देने में सक्षम हो सके। अभियोजन पक्ष द्वारा विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से लाए गए दोषारोपण करने वाले साक्ष्य और दोषारोपण सामग्री की ओर अभियुक्त का ध्यान आकर्षित

नहीं करने में विफलता अपने आप में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे को अमान्य और कानून की दृष्टि से बुरा नहीं बना सकती है; पहला, यदि उसे दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, उसे यह समझाने का अवसर दिया गया था कि वह उसके खिलाफ अभियोजन मामले के संबंध में क्या कहना चाहता था और दूसरा, इस तरह की चूक ने उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। अभियुक्त पर यह स्थापित करने का भार है कि उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाले दोषारोपण करने वाले साक्ष्य और प्रेरक सामग्री से उसे अवगत नहीं कराने से एक पूर्वाग्रह पैदा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।"

26. यहां ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के फैसले इस सुसंगत दृष्टिकोण को दिखाएंगे कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की दोषपूर्ण जांच अपने आप में विचारण को दूषित नहीं करती है। अभियुक्त को इस तरह से उसके प्रति हुए पूर्वाग्रह को स्थापित करना चाहिए। यह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर है कि धारा 313 के अनुसार उसकी जांच नहीं होने के कारण उसके साथ गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है।

27. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, यानि कथित आत्महत्या के तुरंत बाद अभियुक्त ने पुलिस को उसकी अप्राकृतिक मौत के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी; पीडब्ल्यू-10 का बयान कि दरवाजा अंदर से बंद किया गया था और बाहर से धक्का दिए जाने पर यह नहीं खुला; और विचारण न्यायालय ने माना कि अभियुक्त लियाकत को घटना के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उसे केवल 15.5.2000 पर ही गिरफ्तार किया जा सका। उच्च न्यायालय की राय है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त ने अपने बयान में ये सभी परिस्थितियां नहीं बताईं, जिसने मुकदमे को दूषित कर दिया।

28. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटि में पड़ गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कथित आत्महत्या के तुरंत बाद अभियुक्तों ने उसकी अप्राकृतिक मौत के बारे में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है और अभियुक्त इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने विस्तृत रूप से अभियुक्तों से सवाल पूछे हैं और उनका विस्तार से जवाब दिया गया है। अभियुक्त को घटना से पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है,

जिसमें यह भी शामिल है कि अभियुक्त लियाकत का प्रदर्श 14,15,16 और 17 से सामना कराया गया। नतीजा यह हुआ कि फरार आरोपी लियाकत को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जवाब में, अभियुक्त ने कहा "पता नहीं"। यही जवाब अभियुक्त अजीम खान ने भी दिया।

29. न्यायालय ने अभियुक्तों को हुई घटना, घटनाओं के क्रम और अभिलेख पर लाई गई साक्ष्य सामग्री के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से अवगत कराया। अभियुक्त इन सभी साक्ष्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह सवाल नहीं उठाया कि धारा 313 के तहत परीक्षण में उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। अभियुक्त पर यह स्थापित करने का भार है कि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाले सभी दोषपूर्ण साक्ष्यों और प्रेरक सामग्री से अवगत नहीं होने से पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। तत्काल मामले में, हमारा निश्चित विचार है कि अपीलार्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता नहीं हुई है।

30. प्रत्यर्थी -राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर गौर किया है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां मामले को नए सिरे

से निर्णय लेने के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।

32. इससे पहले चर्चा किए गए मामले और कानून के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने और मामले को फिर से विचारण हेतु और नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजने में कानूनी रूप से गलती की है। यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ उच्च न्यायालय को गुणागुण के आधार पर अपील पर निर्णय लेना चाहिए।

33. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील का निपटारा करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और कानून के अनुसार गुणागुण के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं। अपीलार्थी मामले में उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जमानत पर रहेंगे।

न्यायाधिपति एम. वाई. इकबाल

न्यायाधिपति अभय मनोहर सप्रे

नई दिल्ली

26 सितंबर, 2014

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।